सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020

छात्रोपयोगी संकलन

संकलन

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय

गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय - भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नयी और भविष्योन्मुखी दृष्टि

उच्चतर शिक्षा के बारे में इस नीति का मुख्य ज़ोर निम्नलिखित बिंदुओं पर होगा :

- उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एंव बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एचईआई कलस्टरों/नॉलेज हबों में स्थानांतरित करना
- उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या उससे भी अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा।
- विद्वानों और साथियों के जीवंत समुदाय निर्माण और विषयों की बीच उपजी खाईयों को पाटना
- छात्रों को उनके सम्पूर्ण मानसिक और चहुमुखी (कलात्मक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक और खेल) विकास करने में सक्षम, सक्रिय अनुसंधान समुदायों अन्तर-अनुशासनिक अनुसंधान सहित को विकसित करने, और संसाधनों, सामग्री और मनुष्य की कार्य कुशलता की बढ़ोतरी करना
- वंचित क्षेत्रों में पूर्ण उपलब्धता, न्यायसंगतता और समावेश के लिए उचित संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित और विकसित किए जायेंगे।
- 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचआई) होगा।
- श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जायेंगे, जिनके निर्देश का माध्यम स्थानीय/भारतीय भाषाएं या द्विभाषिक होगा।
- इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50 % करना होगा।
- क्षमता निर्माण का एक बड़ा भाग मौजूदा एचईआई को समेकित, महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और बेहतर बनाने के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की सीटें, पहुँच और सकल नामांकन अनुपात बढाने एवं जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने (एसडीजी) हेतु मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन कोर्स को संचालित करने का अवसर होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो।
- सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों (और उनके घटक) के किसी भी डिप्लोमा या डिग्री के मानक और गुणवत्ता, एचईआई के परिसर में संचालित उच्चतम गुणवता कार्यक्रमों के समतुल्य होंगे।
- ओडीएल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी सहायता की जाएगी।

समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर

एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा मनुष्य की सभी क्षमताओं- बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक तथा नैतिक - को एकीकृत तरीके से विकसित करती है।
ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में मदद करेगी

- कला, मानविकी भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान
- व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रो में महत्पूर्ण 21 वीं सदी की क्षमता
- सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता
- व्यवहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स). जैस 'सम्प्रेषण, चर्चा, वाद-विवाद और एक चुने हुए क्षेत्र या क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता

- कल्पनाशील ओर लचीली पाठ्यक्रम संरचनाए अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी, और कई प्रवेश और निकास बिन्दुओ के विकल्प होंगे, जिससे आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा ।
- बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयो में स्नातक स्तर (मास्टर और डॉक्टरेट) की शिक्षा, कठोर अनुसंधान-आधारित विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-साथ अकादमिक (शिक्षा जगत), सरकार और उद्योग सहित, बहु-विषयक कार्यों के अवसर भी प्रदान होंगे।
- देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानो (एचईआई) में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत-विद्या, कला, नृत्य, नाट्यकला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद एवं व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहु-विषयक, भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित आरै मजबूत किया जाएगा।
- इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में क्रेडिट दिया जायेगा।
- उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने ही संस्थानों में या अन्य उच्चतर शिक्षा /शोध संस्थानों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएंगे । जैसे-स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकार, शिल्पकार आदि के साथ इंटर्नशिप और अध्यापको और शोधार्थियो के साथ शोध इंटर्नशिप ताकि छात्र सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष के साथ जुड़ें और साथ ही साथ, स्वयं के रोजगार की संभावनाओ को बढ़ा सके।

डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना

- स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी। जिसमें उपयुक्त प्रमाणपत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर
    - व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट
    - 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा
    - 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री
    - 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहु-विषयक शिक्षा का अनुभव लेने के अवसर प्रदान करता है।
- एक अकादेमिक क्रेडिट बैंक (एसीबी) स्थापित किया जाएगा जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके।
- यदि छात्र एचईआई द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र (क्षेत्रों) में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिगी भी दी जा सकती है।

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के विभिन्न प्रारूप

1. ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होनें 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केन्द्रित हो
2. विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया है, उनके लिए एक वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है
3. 5 वर्षों का एक एकीकृत स्नातक / स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है।
4. पीएच-डी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।
5. एम.फिल कार्यक्रम को बदं कर दिया जाएगा।
6. उच्चतर शिक्षण संस्थान, स्टार्ट अप, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग अकादेमिक जुड़ाव और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, अंतर-विषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करेंगे।

7. संक्रामक रोगों और वैश्विक - महामारियों के परिदृश्य को देखत हुए संक्रामक रोगों, महामारी विज्ञान, वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान
8. एनआरएफ, उच्चतर शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, ओर अन्य अनुसंधान संगठनों से इस तरह के एक जींवत अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को सक्षम करने और समर्थन करने में मदद करने के लिए कार्य

सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्रों को सहयोग

- उच्चतर शिक्षा के व्यापक ढाँचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठयक्रम, शिक्षण विधि और आंकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्ता, जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल), ऑनलाइन और पारम्परिक कक्षा-कक्ष शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
- छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायों द्वारा इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विद्या को रचा जायेगा।
- प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लक्ष्यों तक पहुँचाने के लिए रचनात्मक आंकलन का उपयोग किया जाएगा।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियां भी तय की जाएगी जिनमें अंतिम रूप से प्रमाणन भी शामिल है।
- नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को संशोधित किया जाएगा।
- उच्चतर शिक्षण संस्थान एक मानदंड-आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे, जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्र की उपलब्धि का आंकलन करेगा जिससे प्रणाली निष्पक्ष बनेगी और परिणाम अधिक तुलनीय होंगे।
- हाइ-स्टेक परीक्षाओं से और अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता
    - विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित किये जाएंगे, और इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन दिए जाएंगे।
    - सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक अकादमिक और करियर परामर्श उपलब्ध होगा, साथ ही साथ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी परामर्शदाता होंगे।

अंतर्राष्ट्रीयकरण

- विदेश से आने वाल छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए, विदेशी छात्रों की मेज़बानी करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा।
- उच्चतर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान / शिक्षण सहयोग और संकाय/छात्र आदान-प्रदान की सुविधा को बढ़ाया जाएगा साथ ही विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसी तरह चुनिंदा विश्वविद्यालयों (जैसे, दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जायेगी।
- इस तरह सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडो के स्तर पर कुछ उदारता बरती जाएगी।
- भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान, सहयोग और छात्र आदान-प्रदान को विशेष प्रयासों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
- विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित किये गये क्रेडिट यहाँ मान्य होंगे और यदि वह उस उच्चतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार हैं तो इन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा।

छात्र गतिविधि और भागीदारी

छात्र, शिक्षा प्रणाली में प्रमुख हितधारक है। उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए

- छात्रों को खेल, संस्कृति/ कला क्लब, पर्यावरण-क्लब, गतिविधि क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजना आदि में शामिल होन के लिए भरपूर अवसर दिए जाएंगे।
- प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव से जूझने और भावनात्मक तारतम्यता बनाने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होगी।
- ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें आवश्यकतानुसार छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने संस्थानो में सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे।
- छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इन छात्रों की प्रगति को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्र वृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा।
- निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को महत्वपूर्ण संख्या में फ्रीशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश

यह नीति एसईडीजी पर विशष ज़ोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करती है।

सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम -

- एसईडीजी की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण
- उच्चतर जीईआर तथा एसईडीजी के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर - संतुलन को बढ़ावा देना
- विकास की ओर उन्मुख ज़िलों में उच्चतर गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाकर और बड़ी संख्या में, एसईडीजी लिए हुए विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुँच को सुधारना
- उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास करना जो स्थानीय/ भारतीय भाषाओं मे या द्विभाषी रूप से शिक्षण कराए
- सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एसईडीजी को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना
- एसईडीजी के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना
- बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण और विकास।

सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम

- उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इस दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना
- सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना
- उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार
- पाठयक्रम और प्रवेश प्रक्रियाओ को अधिक समावेशी बनाना
- उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोज़गारपरक बनाना

- भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना
- यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं व्हीलचेयर सुलभ और दिव्यांगजनों के अनुकूल हो
- वंचित शैक्षिक पृष्टभूमि से आने वाले विद्यार्थियो के लिए ब्रिज-कोर्स निर्मित करना
- ऐसे सभी विद्यार्थियों को उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रमों के ज़रिए सामाजिक, भावानात्मक और अकादेमिक सहायता तथा सलाह प्रदान करना
- पाठ्यक्रम सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानो के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेडंर पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करना
- भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ बने सभी नियमों को सख्ती से लागू करना
- एसईडीजी से बढ़ती भागीदारी को सुनिश्चित करने से जुड़े विशिष्ट योजनाओं को शामिल करते संस्थागत विकास योजनाओं का निर्माण करना, जिनमें उपरोक्त बिन्दु शामिल हों लेकिन इन्हीं तक सीमित न हो।

व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन

- व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना
- स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे समस्त शिक्षण संस्थानों द्वारा चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा मे एकीकृत करना
- शिक्षा के आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करना, फिर सुचारू रूप से उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाना
- प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो। ऐसा करने के परिणामस्वरूप वो श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित होगा।
- वर्ष 2025 तक, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए लक्ष्य और समयसीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी।
- जीइआर के लक्ष्यों को तय करते वक्त व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वयं ही या फिर उद्योगो और गैर सरकारी संगठनो के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे

- वर्ष 2013 में शुरू की गई डिग्री बी. वोक पूर्व की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमो में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमे 4-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम भी शामिल रहेगा।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करने की अनुमति होगी।
- लोक विद्या, अर्थात् भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयो को व्यावसायिक शिक्षा पाठयक्रमों मे एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।
- जहाँ भी संभव हो, ओडीएल मोड के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठयक्रमों को संचालित करने की संभावना तलाश की जाएगी।

Lakshmibai College, University of Delhi
Ashok Vihar Phase III, Delhi – 110052
Call : +(91)-11-27308598 Email : info@lb.du.ac.in
Website : lakshmibaicollege.in

सत्यमेव जयते

National Education Policy 2020

Student Centric Compilation

Compiled By

Lakshmibai College, University of Delhi

National Education Policy 2020 : A New and Forward-Looking Vision for India's Higher Education

- Higher education plays an extremely important role in promoting human as well as societal wellbeing and in developing India. Higher education significantly contributes towards sustainable livelihoods and economic development of the nation.

- The main thrust of NEP 2020 regarding higher education is to end the fragmentation of higher education by transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities, colleges, and HEI clusters/Knowledge Hubs.

- The aim is to build vibrant communities of scholars and peers, break down harmful silos, enable students to become well-rounded across disciplines including artistic, creative, and analytic subjects as well as sports, develop active research communities across disciplines including cross-disciplinary research, and increase resource efficiency, both material and human.

- More HEIs shall be established and developed in underserved regions to ensure full access, equity, and inclusion. There shall, by 2030, be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district.
- Steps shall be taken towards developing high-quality higher education institutions both public and private that have medium of instruction in local/Indian languages or bilingually.
- The aim will be to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035.
- Institutions will have the option to run Open Distance Learning (ODL) and online programs, provided they are accredited to do so, in order to enhance their offerings, improve access, increase GER, and provide opportunities for lifelong learning.

- ODL programs and their components leading to any diploma or degree will be of standards and quality equivalent to the highest quality programs run by the HEIs on their campuses. Top institutions accredited for ODL will be encouraged and supported to develop high-quality online courses. These courses will be suitably integrated into curricula of HEIs, and blended mode will be preferred.

Towards a More Holistic and Multidisciplinary Education

- Such an education will help develop well-rounded individuals that possess critical 21st century capacities in fields across the arts, humanities, languages, sciences, social sciences, and professional, technical, and vocational fields; an ethic of social engagement; soft skills, such as communication, discussion and debate; and rigorous specialization in a chosen field or fields.

- Imaginative and flexible curricular structures will enable creative combinations of disciplines for study, and would offer multiple entry and exit points, thus, removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for life -long learning.

- Graduate-level, master's and doctoral education in large multidisciplinary universities, while providing rigorous research-based specialization, would also provide opportunities for multidisciplinary work, including in academia, government, and industry.

Departments in Languages, Literature, Music, Philosophy, Indology, Art, Dance, Theatre, Education, Mathematics, Statistics, Pure and Applied Sciences, Sociology, Economics, Sports, Translation and Interpretation, and other such subjects needed for a multidisciplinary, stimulating Indian education and environment will be established and strengthened at all HEIs.

Credits will be given in all Bachelor's Degree programs for these subjects if they are done from such departments or through ODL mode when they are not offered in-class at the HEI.

As part of a holistic education, students at all HEIs will be provided with opportunities for internships with local industry, businesses, artists, crafts persons, etc., as well as research internships with faculty and researchers at their own or other HEIs/research institutions, so that students may actively engage with the practical side of their learning and, as a by-product, further improve their employability.

The undergraduate degree will be of either 3 or 4 -year duration, with multiple exit options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 1 year in a discipline or field including vocational and professional areas, or a diploma after 2 years of study, or a Bachelor 's degree after a 3-year program.

The 4-year multidisciplinary Bachelor's program, however, shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student.

An Academic Bank of Credit (ABC) shall be established which would digitally store the academic credits earned from various recognized HEIs so that the degrees from an HEI can be awarded taking into account credits earned.

The 4-year program may also lead to a degree 'with Research' if the student completes a rigorous research project in their major area(s) of study as specified by the HEI.

Flexibility To Offer
Different Designs Of Master's Programs

2-year Master's program with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3 year Bachelor 's programme	For students completing a 4-year Bachelor 's program with Research, there could be a **1-year Master's program**	There may be an **integrated 5-year Bachelor's/Master's program**

Undertaking a Ph.D. shall require either a Master's degree or a 4-year Bachelor's degree with Research.

The M.Phil. programme shall be discontinued.

HEIs will focus on research and innovation by setting up start-up incubation centres; technology development centres; centres in frontier areas of research; greater industry-academic linkages; and interdisciplinary research including humanities and social sciences research.

Given the scenario of epidemics and pandemics, Research in areas of infectious diseases, epidemiology, virology, diagnostics, instrumentation,vaccinology and other relevant areas will be undertaken. HEIs will develop specific hand holding mechanisms and competitions for promoting innovation among student communities. The National Research Foundation (NRF) will function

to help enable and support such a vibrant research and innovation

culture across HEIs, research labs, and other research organizations

Optimal Learning Environments and Support for Students

Curriculum and Pedagogy

- In order to promote creativity, institutions and faculty will have the autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy, and assessment within a broad framework of higher education qualifications that ensures consistency across institutions and programs and across the ODL, online, and traditional 'in-class' modes.

- Curriculum and pedagogy will be designed by institutions and motivated faculty to ensure a stimulating and engaging learning experience for all students.

Continuous Assessment

- Continuous formative assessment will be used to further the goals of each program.
- All assessment systems shall also be decided by the HEI, including those that lead to final certification.
- The Choice Based Credit System (CBCS) will be revised for instilling innovation and flexibility.
- HEIs shall move to a criterion -based grading system that assesses student achievement based on the learning goals for each program, making the system fairer and outcomes more comparable.
- HEIs shall also move away from high -stakes examinations towards more continuous and comprehensive evaluation.

Student Support

- For students from socio-economically disadvantaged backgrounds, Universities and colleges will thus be required to set up high –quality support centres and will be given adequate funds and academic resources to carry this out effectively.

- There will also be professional academic and career counselling available to all students, as well as counsellors to ensure physical, psychological and emotional well-being.

INTERNATIONAL STUDENTS AND NEP 2020

An International Students Office at each HEI hosting foreign students will be set up to coordinate all matters relating to welcoming and supporting students arriving from abroad.

Research/teaching collaborations and faculty/student exchanges with high-quality foreign institutions will be facilitated, and relevant mutually beneficial MOUs with foreign countries will be signed.

High performing Indian universities will be encouraged to set up campuses in other countries, and similarly, selected universities e.g., those from among the top 100 universities in the world will be facilitated to operate in India.

A legislative framework will be put in place, and such universities will be given special dispensation regarding regulatory, governance, and content norms on par with other autonomous institutions of India.

Furthermore, research collaboration and student exchanges between Indian institutions and global institutions will be promoted through special efforts.

Credits acquired in foreign universities will be permitted, where appropriate as per the requirements of each HEI, to be counted for the award of a degree

Student Activity and Participation

- Students are the prime stakeholders in the education system. Vibrant campus life is essential for high-quality teaching-learning processes. Towards this end, students will be given plenty of opportunities for participation in sports, culture/arts clubs, eco-clubs, activity clubs, community service projects, etc.

- In every education institution, there shall be counselling systems for handling stress and emotional adjustments. Furthermore, a systematized arrangement shall be created to provide the requisite support to students from rural backgrounds, including increasing hostel facilities as needed.

- All HEIs will ensure quality medical facilities for all students in their institutions. Financial assistance to students shall be made available through various measures. Efforts will be made to incentivize the merit of students belonging to SC, ST, OBC, and other SEDGs. The National Scholarship Portal will be expanded to support, foster, and track the progress of students receiving scholarships.

Equity and Inclusion in NEP 2020

Steps to be taken by Government:

(a) Earmark suitable Government funds for the education of SEDGs

(b) Set clear targets for higher GER for SEDGs

(c) Enhance gender balance in admissions to HEIs

(d) Enhance access by establishing more high-quality HEIs in aspirational districts and Special Education Zones containing larger numbers of SEDGs

(e) Develop and support high-quality HEIs that teach in local/Indian languages or bilingually

(f) Provide more financial assistance and scholarships to SEDGs in both public and private HEIs

(g) Conduct outreach programs on higher education opportunities and scholarships among SEDGs

(h) Develop and support technology tools for better participation and learning outcomes.

Steps to be taken by HEIs

(a) Mitigate opportunity costs and fees for pursuing higher education

(b) Provide more financial assistance and scholarships to socio-economically disadvantaged students

(c) Conduct outreach on higher education opportunities and scholarships

(d) Make admissions processes more inclusive

(e) Make curriculum more inclusive

(f) Increase employability potential of higher education programs

(g) Develop more degree courses taught in Indian languages and bilingually

(h) Ensure all buildings and facilities are wheelchair-accessible and disabled-friendly

(i) Develop bridge courses for students that come from disadvantaged educational backgrounds

(j) Provide socio-emotional and academic support and mentoring for all such students through suitable counselling and mentoring programs

(k) Ensure sensitization of faculty, counsellor, and students on gender-identity issue and its inclusion in all aspects of the HEI, including curricula

(l) Develop Institutional Development Plans that contain specific plans for action on increasing participation from SEDGs, including but not limited to the above items.

NEP 2020 AND VOCATIONAL EDUCATION

- This policy aims to integrate vocational education programs into mainstream education in all education institutions in a phased manner, to overcome the social status hierarchy associated with vocational education.

- Beginning with vocational exposure at early ages in middle and secondary school, quality vocational education will be integrated smoothly into higher education. It will ensure that every child learns at least one vocation and is exposed to several more.

- This would lead to emphasizing the dignity of labour and importance of various vocations involving Indian arts and artisanship. By 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education, for which a clear action plan with targets and timelines will be developed.

- This is in alignment with **Sustainable Development Goal** (to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all), and will help to realize the full potential of India 's demographic dividend. The number of students in vocational education will be considered while arriving at the GER targets.

Higher education institutions will offer vocational education either on their own or in partnership with industry and NGOs.

The B.Vocational degrees introduced in 2013 will continue to exist, but vocational courses will also be available to students enrolled in all other Bachelor’s degree programs, including the 4-year multidisciplinary Bachelor’s programs. HEIs will also be allowed to conduct short-term certificate courses in various skills including soft skills.

‘Lok Vidya’, i.e., important vocational knowledge developed in India, will be made accessible to students through integration into vocational education courses. The possibility of offering vocational courses through ODL mode will also be explored.

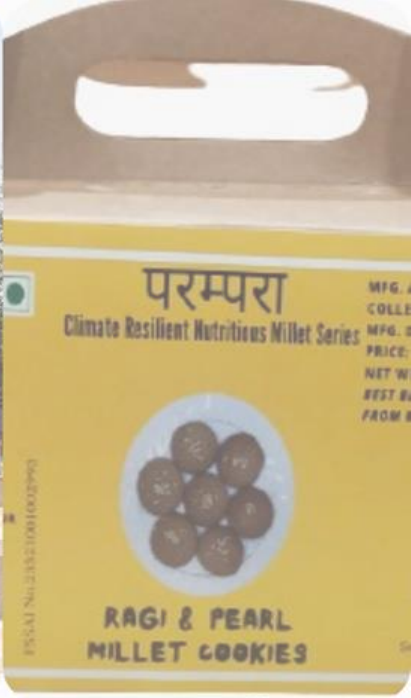

Lakshmibai College, University of Delhi
Ashok Vihar Phase III, Delhi – 110052
Call : +(91)-11-27308598 Email : info@lb.du.ac.in
Website : lakshmibaicollege.in